(ख) दी गई 35.40 लाख रुपये की कुल राशि में से 33.20 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ग) 2.20 लाख रुपये खर्च नहीं किए गए, क्योंकि खतरनाक पदार्थों के प्रबन्ध की विशिष्ट कार्य विधियों का पता नहीं लगाया जा सका।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दी गई निधियों का इस्तेमाल उपकरण खरीदने और तकनीकी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए किया गया। पिछले तीन वर्षों में 30.35 लाख रुपये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा और 2.85 लाख रुपये मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण विभाग द्वारा निम्नलिखित तरीके से खर्च किए :—

	1987-88	1988-89	1989-90
(1) मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग द्वारा उपकरण खरीदने और कर्मचारियों के लिए	2.85	—	—
(2) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :			
(क) कर्मचारियों के वेतन के लिए	1.40	1.00	2.90
(ख) उपकरणों की खरीद के लिए	10.00	0.87	9.88
(ग) खतरनाक अपशिष्टों का प्रबन्ध	—	—	4.80

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों को दूरसंचार सुविधाएं

743. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार की इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर एवं विश्वसनीय संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से, इन क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय विशेष प्राथमिकता दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में किए गए प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) जनजातीय क्षेत्रों में सभी एक्सचेंजों में व्यवहारिक रूप से मांग आते ही टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

(ii) जनजातीय क्षेत्रों मे सभी एक्सचेंजो को आटोमेटिक बनाना ।

(iii) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र मे सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों मे जो दूर संचार सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न नुसार है :--

क्र०स०	मद	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	बिहार
1.	निवल स्थानीय स्विचन क्षमता	21150	52000	19100
2	सीधी एक्सचेंज लाइनें	14800	41700	18500
3.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	प्रत्येक ग्राम पचायत मे एक		

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को अनुदान

744 **श्री अजीत जोगी** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सडक निधि के अंतर्गत 3 अक्तूबर, 1989 को केन्द्र सरकार के पास वर्ष 1989-90 तथा आठवी पचवर्षीय योजना के लिये 92 83 करोड रुपये के प्रस्ताव भेजे गये है,

(ख) क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा 500 से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी ग्रामो को मुख्य मार्गों से जोडने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति/वित्तीय सहायता हेतु भेजा हैं,

(ग) मध्य प्रदेश शासन को उक्त राशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा और यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी, और

(घ) क्या 500 से कम जनसंख्या वाले आदिवासी ग्रामों को भी सडको से जोडने के बारे मे केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ मे जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग को, जो कि नॉडल मंत्रालय है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है, तथापि, वे आदिवासी ग्रामों को जोडने के लिए कोई योजना नही चला रहे है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सडक निधि मे वास्तविक वृद्धि, जिसके आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अभी नहीं हुई है इसलिए इन प्रस्तावो पर अनुमोदन के लिए कार्यवाही नही की गई है ।

(घ) जी, नही ।

मध्य प्रदेश में सड़क विकास के लिये विश्व बैंक सहायता

745. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश सरकार की इस वर्ष सडक विकास के लिये विश्व बैंक से कुल कितनी ऋण सहायता प्राप्त होने की संभावना है,